



जटिल है- राजनीति के अपराधीकरण को रोका जाना

एक समय था जब सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेता आदर्श हुआ करते थे। वे न गरीबी को छिपाते थे, न समृद्धि को, और न इतराते थे। पर अब समय परिवर्तित हो चुका है। गरीबों की सेवा के नाम पर राजनीति करने वाले रातोंरात घनिक बन जाने वाले ये राजनीति के खिलाड़ी उद्योग पतियों को भी मात दे रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा घोषित सम्पति का व्यौरा बुद्धिजीवियों को चाँका रहा है जिसे फैलते भृष्टाचार का नासूर कहा जाना अतिशयोकृत नहीं होगा। प्रत्याशियों के आय के स्रोतों को भी चुनाव आयोग द्वारा घोषित कराया जाना चाहिये।

आज कोई इस वास्तविकता से इंकार नहीं कर सकता कि अन्य क्षेत्रों के अलावा राजनैतिक क्षेत्र में असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों का बोलबाला है। घनबल और बाहुबल ने अपना शिकंजा कस रखा है जिसके कारण आम आदमी सिर्फ निरीह की श्रेणी में है। लोकतंत्र इसके कारण एक मखौल बनता जा रहा है। क्या यही है स्वराज्य की सही कल्पना? इस भयानक संकट से त्राण पाने, परिष्कार एवं परिहार के लिये क्या कोई कदम उठाना संभावित है? जातिवाद वंशवाद तथा अपराधी करण की बेल धटने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही है।

राजनीति का अपराधी करण और अपराधियों का राजनीतिकरण आज गंभीर समस्या बन चुकी है। यही कारण है जब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था को दागी नेताओं के मामले निपटाने के लिये विशेष अदालतें गठित करने का परामर्श देना पड़ा है। भारतीय लोकतंत्र के दागदार मामलों में यह भी देखने को मिला कि जेल की सलाखों में रहने के बाद भी चुनाव महाकौशल संदेश

लड़े गये। गंभीर अपराधों में सजा प्राप्त संसद और विधानसभा के सदस्य बने। इस प्रकार के तमाम मामलों को राजनीति में आयी गिरावट के रूप में देखा जाना चाहिये था। बाहुबलियों ने भी सत्ता

तक पहुँचे भी। **डॉ. किशन कछवाहा** की सेवा नबल और सत्ताबल

का दुरुपयोग होते तो हम सब लम्बे समय से देखते ही आ रहे हैं। संसद और विधानसभाओं में दो हजार के आसपास दागी चेहरे वाले सांसद और विधायक हैं। ये लोकतंत्र को पलीता लगाने में क्या अपना योगदान नहीं दे रहे? ले किन कोई भी राजनीतिकदल इस ओर ध्यान नहीं दे रहा — यही सच्चाई है। क्या अपराधियों को, दोषियों को राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता? किसे है राजनीति को साफ — सुधरा बनाये रखने की चिन्ता?

देशभर के विधानसभा से 4215 विधायक लोकसभा से 543 सांसद जनता द्वारा चुनकर आते हैं। सात राज्यों में विधानपरिषदें भी अस्तित्व में हैं। राज्यसभा में 238 (सदस्य भी) सांसद कहे जाते हैं। इनमें करोड़पतियों — अरबपतियों की संख्या ज्यादा है। जनतंत्र धनतंत्र में बदलता जा रहा है। सबसे अधिक चिन्ता का विषय यह है कि इस लोकतंत्र में गरीब या कम पैसे वाला व्यक्ति देश की गरीब जनता का प्रतिनिधि कैसे बन सकेगा? दूसरी ओर राजनीति में ईमानदारी तेजी से लुप्त होती जा रही है। जन प्रतिनिधियों का रहन—सहन और उनकी जीवन शैली देखकर भी समझा जा सकता है। भारतीय गणतंत्र की नींव में जिन

आधार—शिलाओं, सत्य अहिंसा, समाजसेवा राष्ट्र की एक ता, अखंडता पंथ निरपेक्षता तथा सर्वांगीण विकास को चुन—चुन कर रखा था उन्हे भुला दिया गया है। हर कदम पर असत्य का सहारा लेते ही दिख रहा है। जनता को की। बहुतेरे सत्ता

तक पहुँचे भी। **डॉ. किशन कछवाहा** की सेवा

में ह गी

महसूस होने लगी है। अधिकतर राजनैतिक दलों का चाल चलन भारत के लोकतंत्र के लिये चिन्ता का विषय है। राजनीति के अपराधी करण पर चिन्ता तो जताई जाती है, पर अमल कौन कर रहा है? राजनैतिक दलों में भी आंतरिक लोकतंत्र बचा कहाँ है? अपराधियों की घुसपैठ रोकने की पहल नहीं हुयी। इसीलिये तो सर्वोच्च न्यायालय को दिशा निर्देशजारी करने वाध्य होना पड़ा है।

राजनीति मुनाफे वाला धन्धा बन जाने के कारण आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। जनता ने अपने नेताओं को बेशुमार दौलत बटोर कर मालामाल होते देखा है। चापलूसों की फौज से घिरे देखा है। अपराधी राजनेताओं को संरक्षण मिलने के कारण बढ़ते उथले और ओछेपन के चलते असहाय आम आदमी के ऊँसू क्या पीछे जा सकते हैं? इसे गहराई से समझा जाना चाहिये। बाहुबलियों, घनपतियों की राजनीति में बढ़ती दिलचस्पी और बढ़ती संख्या ने लोकतांत्रिक और आर्थिक प्रक्रिया को तहस—नहस किया है, वही इनके सहयोग से उपजे भृष्टाचार ने नैतिकता की जड़ों को खोखला किया है, जिसके कारण हमारा जनतंत्र भटका हुआ सा लगता है। इससे ज्यादा कमाई किसी और काम में नहीं है इसलिये बढ़ावा मिला है। खतरा छ: प्रतिशत और लाभ 94 प्रतिशत।

(1)

अत्यन्त समृद्धशाली यानी करोड़पति—अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान एशिया प्रशान्तक्षेत्र में चौथा है। इस समय यहाँ 2,19,000 अति अमीर लोग हैं। मिलेनर उसे माना जाता है, जिसकी संपदा दस लाख डालर (6.5 करोड़ रुपये) है। केपजैमिनी की रिपोर्ट के अनुसार इन समृद्धशाली व्यक्तियों की कुल सम्पदा 877 अरब डालर है।

सन् 2014 के चुनावी हलफनामों के अनुसार देश के 1581 सांसदों — विधायकों पर मामले दर्ज हैं। इतनी अधिक संख्या में अपराधिक पृष्ठभूमि के जनप्रति निधियों की उपस्थिति एक ओर जहाँ भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र बचा कहाँ है? अपराधियों की घुसपैठ रोकने की पहल नहीं हुयी। इसीलिये तो सर्वोच्च न्यायालय को दिशा निर्देशजारी करने वाध्य होना पड़ा है। राजनीति मुनाफे वाला धन्धा बन जाने के कारण आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। जनता ने अपने नेताओं को बेशुमार दौलत बटोर कर मालामाल होते देखा है। चापलूसों की फौज से घिरे देखा है। अपराधी राजनेताओं को संरक्षण मिलने के कारण बढ़ते उथले और ओछेपन के चलते असहाय आम आदमी के ऊँसू क्या पीछे जा सकते हैं? इसे गहराई से समझा जाना चाहिये। बाहुबलियों, घनपतियों की राजनीति में बढ़ती दिलचस्पी और बढ़ती संख्या ने लोकतांत्रिक और आर्थिक प्रक्रिया को तहस—नहस किया है, वही इनके सहयोग से उपजे भृष्टाचार ने नैतिकता की जड़ों को खोखला किया है, जिसके कारण हमारा जनतंत्र भटका हुआ सा लगता है। इससे ज्यादा कमाई किसी और काम में नहीं है इसलिये बढ़ावा मिला है। खतरा छ: प्रतिशत और लाभ 94 प्रतिशत।

संभव है आपराधिक मामलों की जाँच के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अदालत गठन की वकालत के क्रियान्वयन के पश्चात इसमें सुधार की आशा जग सके। जब इन विशेष अदालतों द्वारा राजनेताओं से जुड़े

28 नवम्बर निर्वाणदिवस-विशेष लेख

समरसता के प्रणेता महात्मा फुले

पूना (महाराष्ट्र में एक अत्यन्त गरीब परिवार में जन्मे सामाजिक सुधार के आदि प्रवर्तक महात्मा ज्योतिबा फुले ने विरोध की परवाह किये बिना स्थान स्थान पर विद्यालयों की स्थापना के साथ—साथ समाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनों का नेतृत्व किया। ग्रन्थों, पुस्तकों, कविताओं का लेखन कार्य जारी रखते हुये अतिशूद माने जाने वाले समाज की कन्याओं एवं महिलाओं के लिये पाठशालाओं की स्थापना का क्रांतिकारी कदम उठाया। इस महापुरुष ने समाज सुधार, धर्म, समाजसेवा महिला शिक्षा, विधवा उद्धार, छुआछूत, किसान—मजदूर आन्दोलन, अछूतोद्धार, मानवीय समानता, समरसता, अंधविश्वास की जड़ों को समाप्त करने अहर्निशि जुटकर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस समरसता के महान साधक महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पूना के पास खानवाडी ग्राम में एक अत्यन्त सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। एक वर्ष की आयु होने पर माता के देहान्त के कारण उनके पालन पोषण का भार पिता पर आ पड़ा था। पिता गौविन्दराम फूलमाली परिवार से थे इसलिये ज्योतिबा भी फुले कहलाये।

सर्व प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस देश में समाज सुधार

और दलितवर्ग के उत्थान के लिये एक अभियान की शुरूआत की। इसके साथ ही धर्म और संस्कृति के मूल स्वरूप के शोध के लिये एक महान परम्परा का शुभारम्भ किया। ज्योतिबा के पिता ने भी अपनी गरीबी की परवाह न करते हुये अपने पुत्र की उच्च शिक्षा के लिये पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि विद्या और ज्ञान किसी एक वर्ग की थाती नहीं है। उसका लाभ जो चाहे ले सकता है।

जिस समाजसेवा की दिशा में वे चल पड़े थे, उसमें एक घटना ने तूफानी क्रान्ति ला दी। वे अपने एक ब्राह्मण मित्र के आग्रह पर उसकी बारात में शामिल होने चले गये। लेकिन वहाँ माली जाति—वर्ग का होने के कारण उपहास और तिरस्कार का पात्र बनना पड़ा। उसीक्षण ज्योतिबा ने संकल्प लिया कि जब तक समाज में जाति सम्बन्धी ऊँच—नीच की बुराईयों विद्यमान है, तब तक इन बुराईयों को समाप्त करने तक प्रयासरत रहेंगे।

उन्होंने अपनी अशिक्षित पत्नी को भी पढ़ाया। इस उद्देश्य को लेकर कि वह उनके जीवन पथ पर उनके संकल्प को पूरा करने में सहयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने महिला शिक्षा के लिये भी

अपने प्रयास प्रारंभ कर दिया। उन्हें साथियों ने उच्च वर्ग द्वारा विरोध किये जाने पर समझाने का प्रयास किया लेकिन उनके सुझाव के प्रत्युत्तर बने थे, शिवाजी ने कई किले में कहा कि नेपोलियन 23 साल की आयु में बिग्रेडियर मुगलों से छीन लिये थे, सन्त ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीका तैयार कर दी थी। मेरी अवस्था इसी काम के लिये है। यदि नेकी की राह पर चलते हुये मृत्यु मिले तो उससे भी मुझे संतोष ही होगा। ज्योतिबा ने कन्याशिक्षा के अपने प्रयास जारी रखे। स्थान स्थान पर कन्या शालाओं की स्थापना करायी। यद्यपि उस समय उच्च वर्ग कन्याओं को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं था। उनकी खूब आलोचना हो रही थी, मार डालने की धमकी दी गयी। महिलाओं की दशा अत्यंत चिन्ता जनक थी। धार्मिक अन्धविश्वास एवं पाखण्ड का अधिक प्रभाव था।

मार्टिन लूथर, प्रो. विल्सन, विलियम जोन्स आदि का साहित्य पढ़ने के बाद वे इस निश्चय पर पहुँचे कि जब तक पिछड़े समाज के लोगों में बुद्धि, स्वाभिमान और सामर्थ्य का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस समाज का कल्याण सम्भव नहीं है। अतः ज्योतिबा उस दिशा में सक्रिय हो गये। सन् 1855 में लिखा नाटक 'तृतीय रत्न, 1872 में गुलामगिरी ग्रन्थ का व्यापक प्रभाव

पड़ा। सन् 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की।

सन् 1855 में लिखी 'अछूतों की कैफियत' नामक पुस्तक ने चमत्कार ही कर दिया। वीर शिवाजी और जार्ज वाशिंगटन के जीवन से वे बहुत प्रभावित थे। इन्हीं दिनों उन्हें सर थामस द्वारा लिखी पुस्तक' मानव का अधिकार पढ़ने को मिल गयी। इस पुस्तक ने उन पर मिट प्रभाव छोड़ा। इस पुस्तक ने उनके मन में गुलामी के प्रति एक विशेष प्रकार का आक्रोश भर दिया। उन्होंने अपने पिछड़े और दलित बन्धुओं की अज्ञानता को दूर करने के लिये अंतिम क्षणों तक अपने पूरे प्रयासों को गति देते रहे। सन् 1890 के 28 नवम्बर को इस महामानव ने इस संसार से विदा ले ली। वे अपना पूरा जीवन धर्म और समाज की सेवाओं में खपाकर सदा के लिये अमर हो गये। उनकी समाज सेवा सदा के लिये प्रेरणादायक और स्मरणीय रहेगी। आगे चलकर 14 अप्रैल 1891 को जन्मे दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसी राह पर चलते हुये महात्मा फुले के सपनों का साकार किया। डॉ. अम्बेडकर ने यह भी कहा कि महात्मा फुले का अनुयायी कहलाने में मुझे गौरव का अनुभव होता है। उन्होंने इस महान विभूति को अपना तीसरा गुरु माना था।

— डॉ. किशन कछवाहा

पुरस्कार

किया जिससे हमे यह पता चलता है कि आर्थिक फैसले लेने वाले

ऐसे अधिकतर निर्णय मानवीय विशेषताओं पर लिए जाते हैं। ज्ञातव्य

भारत सरकार के नवम्बर 2016 में नोटबंदी के फैसले का समर्थन

किया था। उन्होंने ट्वीट (8 नवम्बर, 2016) किया था कि — यह वही नीति है, जिसका मैं लंबे समय से समर्थन करता रहा हूं। यह कैशलेस तंत्र की तरफ पहला कदम है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सही प्रयास है।

**10.000
संस्कृत
शब्द**

हैं लिथुआनियाई भाषा में जिन्हें संकलित करने का कार्य जारी है। यह जानकारी भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए लिथुआनियाविदेश मंत्री लिनास लिंकेविसियस ने दी। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को संस्कृत—लिथुआनियाई माला भी प्रस्तुत की जो एक शब्दकोश और जिसमें संस्कृत और लिथुआनियाई भाषा के 108 सामान्य शब्द संकलित हैं।

वर्ष 2017 का अर्धशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर को दिया गया है। पुरस्कार के तहत उन्हें 11 लाख अमेरिकी डॉलर (7 करोड़ रुपए से अधिक) की राशि प्रदान की जाएगी। नोबेल पुरस्कार समिति ने घोषणा करते हुए कहा कि थेलर को अर्थशास्त्र के मनोविज्ञान को समझने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने सीमित तार्किकता का सिद्धांत विकसित महाकोशल संदेश

हमेशा तर्कसंगत नहीं होते बल्कि

है कि थेलर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने

(2)

वंचित पुजारी

तिरुवला (केरल) के पास मनप्पुरम शिव मंदिर के गर्भगृह में 9 अक्टूबर को प्रभार संभालने के साथ ही येदु कृष्णन ने वंचित वर्ग से केरल के पहले पुजारी के तौर पर इतिहास रच दिया। ज्ञातव्य है कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड के तहत 36 गैर ब्राह्मणों के नामों की हाल ही में विभिन्न मंदिरों में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी बोर्ड राज्य में कम से कम 1,248 मंदिरों का प्रबंधन संभालता है जिसमें सबरीमाला का प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर भी शामिल है। संस्कृत में स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्र होने के साथ-साथ कृष्णन ने तंत्रशास्त्र में 10 साल का प्रशिक्षण भी लिया है। बोर्ड की ओर से पुजारी नियुक्त किए जाने के लिए जिन 36 गैर ब्राह्मणों के नामों की सिफारिश की गई थी, उनमें छह वंचितों में कृष्णन भी शामिल हैं। केरल 12 नवम्बर को गैर ब्राह्मणों के मंदिर प्रवेश घोषणा की 81 वीं वर्षगांठ मनाने वाला है।

पिछले दिनों ग्राम व ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान, चिक्कूट द्वारा 17 अक्टूबर, से 21 अक्टूबर तक ग्रामश्री मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीनदयाल शोध संस्थान के विभिन्न प्रकल्पों के प्रयासों की झाँकियां लगाई गई जिसे लोगों की काफी सराहना मिली। साथ ही सुदूर गांवों के संसाधनों से बनाये गये उत्पाद के स्टाल भी लगाए गये। ग्रामश्री मेले का उद्घाटन धनतेरस के शुभ अवसर पर दीनदयाल शोध संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता पद्माकर मालवीय द्वारा महापुरुषों की प्रदर्शनी के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर दिया गया। संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन ने इस अवसर पर कहा कि गत 23 वर्षों से दीनदयाल शोध संस्थान दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिये किसी न किसी रूप में मेले का आयोजन करता रहा है। इस प्रकार क मेले में खासतौर पर लोगों के लिये रामायण का बड़े परदे पर प्रदर्शन विशेष महत्व रखता है।

आध्यात्मिक मानवतावाद

वर्तमान समय में मनुष्य जैसे—तैसे शिष्टाचार तो निभा लेता है, परन्तु जब बारी सदाचार को निभाने की आती है, तब वह औंधे मुँह गिर पड़ता है। स्वार्थलिप्सा, वासना और अहंता उसे दबोच लेते हैं। यहीं वजह है कि अच्छा करने के इरादे से निकलने वाले लोग भी कुछ दूर चल कर बुरा करने लगते हैं। उनकी आंतरिक दुर्गम्भ पूरे समाज में सङ्गँध फैलाने लगती है। इसे दूर करने के लिये आध्यात्मिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक चिन्तन और आध्यात्मिक साधना की जरूरत पड़ती है। इसे अपना लेने पर मानव जीवन सचमुच कल्याणकारी बन जाता है। उसमें आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण के फूलों की खुशबू महकने लगती है, फिर वह संवेदनाओं के संवेग से संचालित होता है। ऐसे व्यक्ति ही तो जाति, वंश और नर-नारी का भेद मिटाकर जनसेवा के लिये आगे बढ़ते हैं। इन्होंने के द्वारा ही भविष्य में नारी अस्मुदय का उद्घोष होना है।

●
समस्याओं का समाधान भले ही आज हो या आज से हजार वर्ष बाद, पर उनका समाधान मात्र एक ही उपाय से संभव होगा कि मनः स्थिति में संव्याप्त अवॉच्नीयता को पूरी तरह बुहार फेंका जाए और ऐसा कुछ शक्तिशाली चिन्तन उभारा जाए, जो प्रस्तुत उलटे प्रवाह को अपनी प्रचंड शक्ति के सहारे उलटकर सीधा कर सके।

●
स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर गए तो उनकी भेंट एक वृद्ध पुरुष से हुई। वे 75 वर्ष के थे, परन्तु अत्यंत उत्साह के साथ जर्मन भाषा सीख रहे थे। स्वामी रामतीर्थ ने पूछा—“आप इस उम्र में यह भाषा सीखकर क्या करेंगे?” “वृद्ध बोले—“स्वामी जी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने प्राणिविज्ञान में उच्चतर उपाधि प्राप्त की है। जर्मन भाषा में इस विषय में कई अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मैं उनका जापानी में अनुवाद करूँगा, ताकि हमारे देशवासी भी उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।” उनके उत्साह व राष्ट्र की प्रगति के प्रति नकी उत्कट अभिलाषा देखकर स्वामी रामतीर्थ ने श्रद्धासिक्त होकर उनके पैर छुए और बोले—“मैं समझ गया कि जापान के व्यक्ति ही असली कर्मयोग को पहचानते हैं। कर्मयोग की सच्ची परिभाषा आपका जीवन ही है। जहाँ आप जैसे कर्मठ लोग विद्यमान हैं, उस राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता।

पहला

स्वतंत्रता संग्राम

सरकार ने स्वीकार किया है कि 1817 में संगठित पाइका संग्राम ही अंग्रेजों के खिलाफ देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और 2018 में इसे पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1857 के सिपाही विद्रोह को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। लेकिन तथ्यों के आधार पर 1817 में ओडिशा में हुआ संगठित पाइका संग्राम ही देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम जान पड़ता है। जावड़ेकर ने पाइका संग्राम द्विशताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यह बात कही।

जवान अब चीनी भाषा सीख रहे...

भारत — चीन सीमा पर टकराव की बढ़ती घटनाओं को देखते हुये आईटीबीपी के जवानों को अब चीनी भाषा सिखाई जा रही है ताकि वे चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकें।

वेद अध्ययन केंद्र की योजना.

केरल के सबसे बड़े मंदिर संगठन त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी) वेद-वेदांत और तंत्र के सम्बूधित अध्ययन के लिए एक विशेष कॉलेज और अध्ययन केंद्र खोलने पर विचार कर रहा है। ज्ञातव्य है कि टीडीबी दक्षिणी राज्य में सबरीमाला के प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर सहित कम से कम 1,248 मंदिरों का प्रबंध देखता है। टीडीबी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वेद-वेदांत-तांत्रिक अध्ययन केंद्र और वेद-वेदांत कॉलेज में आध्यात्मिकता की प्राचीन पंरपराओं को सिखाने का एक अनोखा केंद्र होगा।

आपराधिक मामलों का निपटारा शीघ्र होगा। देश को जब सन् 47 में स्वतंत्रता मिली थी तब यह विचार नहीं आया होगा कि जिस प्रजातंत्र की कामना के लिये इतनी लम्बी लड़ाई लड़ी गयी, उसका हश्च कुछ ऐसा होगा। आजादी के सत्तर साल बाद भी देश झूठों, फरेबियों की राजनीति का शिकार बना हुआ है। सच्चे और योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है लेकिन वे इन झूठों और फरेबियों के सामने बौने सिद्ध हो रहे हैं, असल प्रश्न की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा? अदालते और गवाह। गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलती – वे प्रभावशाली व्यक्तियों के हठकन्डों के सामने ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाते परिणाम वही होता है – ढाक के तीन पात, गवाह पलट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह गवाहों की सुरक्षा का उपाय करे। विधि आयोग ने भी सुझाव दिये थे। लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे कुछ और अन्यान्य कारणों से सजा का औसत प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2010 में कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना उसका न तो नार्क एनालिसिस टेस्ट हो सकता है और न ही झूठ पकड़ने वाली मशीन का उपयोग किया जा सकता है। अपराधियों को बहुत सी सुविधायें मिली हुयी हैं। राजनीतिक दल भी अनेक मामलों में कठोर कार्यवाही के लिये सहमत नहीं है। फिर प्रश्न यही है कि राजनीति का अपराधी करण और अपराधियों के राजनीति करण को रोका कैसे जा सकेगा?

संविधान पीठ को सौंपी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लेने से संबंधित याचिका गुरुवार को संविधान पीठ को सौंप दी। इस मामले में शीर्ष अदालत के पांच वरिष्ठतम जज सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत ने याचिका पर केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी किया। याचिका में इस मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी निगरानी करने का अनुरोध किया गया है।

वैज्ञानिक शोध के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करें

पणजी केन्द्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने अपने मंत्रालय के तत्त्वधान में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर) द्वारा राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एन.आई.ओ) में हिन्द महासागर: आर्थिक एवं भू-रणनीतिक महत्व विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के विचारों का डी.एन.ए मौजूद है और वह भी बाजपेयी जी की तरह देश को विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहते हैं। आपने आगे कहा कि वह श्री मोदी चाहते हैं कि वैज्ञानिक समुदाय सिर्फ शोधपत्रों के प्रकाशन तक सीमित न रहे, बल्कि अपने शोधों और खोजों से देश की जनता की समस्याओं का समाधान करें।

प्रदूषण की निगरानी के लिए उच्चस्तरी समिति

पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के मद्देनजर वायु प्रदूषण के समाधान का सुझाव देने और उसकी निगरानी के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है। दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से गंभीर स्वास्थ्य चिंताएं पैदा हो रही हैं। मंत्रालय ने प्रभावित राज्य सरकारों से प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रेसपॉन्स ऐक्सन प्लान (जीआरएपी) को भी लागू करने को कहा है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस योजना में सड़कों और निर्माण से जुड़े धूल, कचरा जलाने, बिजली संयंत्र और औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण शामिल है। पर्यावरण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने बताया कि पर्यावरण संचिव की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों पर गौर करेगी। योजना तैयार करने और विभिन्न उपायों को लागू करने के लिये नियमित अंतराल पर इसकी बैठक होगी।

भारत - बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थी। बंधन एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बांग्लादेश के औद्योगिक शहर खुलना के बीच प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। इसका संचालन 177 किलोमीटर लंबे खुलना-कोलकाता रेल मार्ग

संबंध हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों के बीच, उन्हें मजबूत करने की दिशा में गुरुवार को हमने कुछ और कदम उठाए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों के बीच आवाजाही और संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमने

गुरुवार को दो रेल पुलों का भी उद्धाराटन किया है।

सूचना
कृपया आप अपना ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर महाकोशल के ई मेल में भेजने का कष्ट करें ताकि महाकोशल संदेश आपको ईमेल पर प्रेषित किया जा सके।
— सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं-1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफ्सेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान-विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कालोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश। संपादक- डॉ. किशन कछवाहा

Email:- vskjbp@gmail.com

kishan_kachhwaha@rediffmail.com